

आदिवासी एक्सप्रेस

आमजन का एक मात्र हिंदी दैनिक अखबार

फ्रीप्रेस

जुदा हुए कुशाल टंडन और शिवांगी जोशी,
एक्टर ने दी ब्रेकअप की जानकारी,
बोले- कोई पछतावा नहीं



झारखंड

रांची में घटाया सांसद की सड़क
को लेकर बड़ी पहल, पांच जणरुई
सड़कों के निर्माण की माँग

हण्डीबाग

कांग्रेस नेता मुज्जना सिंह ने डीवीसी को
दिया अल्टीमेटम, कहा अगर उगाला
नहीं मिलेगा तो कोयला भी नहीं जाएगा

शहीद जवान सुनील धान के आश्रितों को 2.66 करोड़ की वित्तीय मदद

बिशेष प्रतिनिधि द्वारा

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को काके रोड इंश्ट्रियल क्षेत्र आवासीय कार्यालय में जारखंड जुगाड़ (एसटीएफ) के शहीद अरक्षी सुनील धान के परिजनों ने मूलकारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिजनों को कुल 2 करोड़ 66 लाख 26 हजार 972 रुपये की सहायता राशि प्रदान की। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पुलिस सैलरी फैजेज के तहत 1.20 करोड़ का चेक सौंपा गया, जबकि गुह विभाग द्वारा 1.46 करोड़ रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में क्रेडिट की गई है। मुख्यमंत्री ने दी शहादत को श्रद्धांजलि,

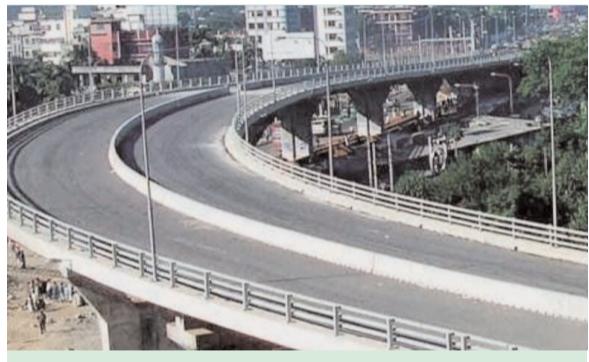


परिजनों से तर्फ इसानुभूति: मुख्यमंत्री ने शहीद की मां भरी फागा उडान, पल्ली मती गंदरी थान और बच्चों से सहानुभूतिपूर्वक बातचीत की और उनके पारिवारिक हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरक्षी सुनील धान ने राज्य के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। राज्य सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। उनकी शहादत को ज्ञारखंड की पर्याप्ति नहीं भूलेगा।

नोकरी का प्रस्ताव, शिक्षा पर जोर: मुख्यमंत्री ने शहीद की पत्नी को अनुकंपा के आधार सरकारी नोकरी का प्रस्ताव दिया। इस पर पत्नी ने कहा कि उनके बच्चे अभी छोटे हैं,

जात हो कि 12 अप्रैल 2025 को चार्डबासा जिले के रातामाटी गांव में चलाए जा रहे नक्सल विशेषी अभियान के दौरान आईटी विस्कोट में अरक्षी सुनील धान गंगीर रुप से चायत हो गए थे। उन्हें गंगीर परिलिप्त कर लाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने वीरता प्राप्त की।

इस अवसर पर गृह विभाग की प्रधान सचिव बदना दादेल, डीआईजी जारखंड जुगाड़ इंडिजॉत महाया, सैनियर डीसीपी सुनील कुमार रंगवार, एसपीआई के उप महाप्रधान मोजर कुमार, मुख्य प्रबंधक विकास कुमार पांडे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



रातुरोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नामकरण पर छिड़ा सियासी संग्राम

संवाददाता द्वारा

रांची। रातुरोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निमांग कार्य पूरा हो चुका है। इसका उद्घाटन पर्ले 19 जून को क्रेस्टाविथ था, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमंत्री मंत्री नितिन गडकरी को व्यस्तता के कारण अब यह कार्यक्रम 3 जुलाई को आयोजित किया जाएगा।

हालांकि यह एलिवेटेड अवर केबल एक आधारभूत संरचना नहीं रह गया है, बल्कि इसका नामकरण सामाजिक, जातीय और राजनीतिक दावेदारी का अखाड़ा बन गया है। विभिन्न वर्ग और समुदाय चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण परियोजना का नाम उनके नायक के नाम पर रखा जाए।

शहीद अधिकारी कुमार साहू के नाम पर एक नायकरण की मांग: राज्यीय युवा विभाग ने केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने मंगलवार का रातुरोड एलिवेटेड कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एलान किया कि 28 अक्टूबर 2020 को लदाख में शहीद हुए अधिकारी कुमार साहू के नाम पर इस फ्लाईओवर का नाम रखा जाना चाहिए।

अधिकारी कुल रूप से मांदर के चोरिया गांव के निवासी थे और औबोसी समुदाय से आते थे। यादव ने कहा कि जब कोई जवान देश के लिए अपनी जान न्योडार करता है, तो उसके नाम पर एक पुल नहीं, पूरा शहर समर्पित किया जा सकता है। यह भी नायकरी को अपनी जान देने के समर्पण में एक लाख लोगों से हस्ताक्षर जुटाने का धूम राखा जाएगा।

महाराजा महराज मुंदा के नाम की जो जारी रहेरा पैरवी: मुंदा समुदाय की ओर से सोशल मीडिया पर एक व्यापक अधियान चलाया जा रहा है, जिसमें फ्लाईओवर का नाम महाराजा महराज मुंदा के नाम पर रखने की मांग की जा रही है। समुदाय का कहना है कि महराजा मुंदा छोटानामगुर के पहले महाराजा थे और उनके ऐतिहासिक योगदान को नई पीढ़ी तक हुंचाना अवलम्बन करता रहा।

शिक्षा संसार के नाम पर खिजरी विधायक की मांग: खिजरी विधायक राजेश कच्छे ने फ्लाईओवर का नाम जारखंड अंडोलन के प्रतीकों और पूर्व मुख्यमंत्री शिख सोरेन (गुरुजी) के नाम पर रखने के बाकल की जोगदान की जाएगी।

विनोद बिहारी महाने के नाम की पेशकश: कुड़ीसी समाज की ओर से जारखंड अंडोलन के अग्रणी नेता विनोद बिहारी महाने के नाम पर फ्लाईओवर का नाम रखने की मांग रही है। उनका कहना है कि महानों का योगदान जारखंड के लिए अतुलनीय रहा है और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

वीर चुनून को लेकर आंदोलन: जारी रही विधायक संघ के अध्यक्ष सोमा उत्तम ने फ्लाईओवर का नाम कोलं विद्रोह के महानायक वीर चुनून भगत के नाम पर रखने की मांग रखते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि बुध भात आदिवासी चेताना और बलिदान के प्रतीक हैं और उन्हें सम्मानित करना चाहिए।

शिक्षा संसार के नाम पर खिजरी विधायक की मांग: खिजरी विधायक रातुरोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निमांग कार्य पूरा हो चुका है। इसका उद्घाटन पर्ले 19 जून को क्रेस्टाविथ था, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमंत्री मंत्री नितिन गडकरी को व्यस्तता के कारण अब यह कार्यक्रम 3 जुलाई को आयोजित किया जाएगा।

हालांकि यह एलिवेटेड अवर केबल एक आधारभूत संरचना नहीं रह गया है, बल्कि इसका नामकरण सामाजिक, जातीय और राजनीतिक दावेदारी का अखाड़ा बन गया है। विभिन्न वर्ग और समुदाय चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण परियोजना का नाम उनके नायक के नाम पर रखा जाए।

शहीद अधिकारी कुमार साहू के नाम पर एक नायकरण की मांग: राज्यीय युवा विभाग ने केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने मंगलवार का रातुरोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम पर रखने की योगदान जारखंड जुलाई 2020 को आयोजित किया जाएगा।

शहीद अधिकारी कुमार साहू के नाम पर एक नायकरण की मांग: राज्यीय युवा विभाग ने केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने मंगलवार का रातुरोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम पर रखने की योगदान जारखंड जुलाई 2020 को आयोजित किया जाएगा।

शहीद अधिकारी कुमार साहू के नाम पर एक नायकरण की मांग: राज्यीय युवा विभाग ने केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने मंगलवार का रातुरोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम पर रखने की योगदान जारखंड जुलाई 2020 को आयोजित किया जाएगा।

शहीद अधिकारी कुमार साहू के नाम पर एक नायकरण की मांग: राज्यीय युवा विभाग ने केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने मंगलवार का रातुरोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम पर रखने की योगदान जारखंड जुलाई 2020 को आयोजित किया जाएगा।

शहीद अधिकारी कुमार साहू के नाम पर एक नायकरण की मांग: राज्यीय युवा विभाग ने केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने मंगलवार का रातुरोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम पर रखने की योगदान जारखंड जुलाई 2020 को आयोजित किया जाएगा।

शहीद अधिकारी कुमार साहू के नाम पर एक नायकरण की मांग: राज्यीय युवा विभाग ने केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने मंगलवार का रातुरोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम पर रखने की योगदान जारखंड जुलाई 2020 को आयोजित किया जाएगा।

शहीद अधिकारी कुमार साहू के नाम पर एक नायकरण की मांग: राज्यीय युवा विभाग ने केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने मंगलवार का रातुरोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम पर रखने की योगदान जारखंड जुलाई 2020 को आयोजित किया जाएगा।

शहीद अधिकारी कुमार साहू के नाम पर एक नायकरण की मांग: राज्यीय युवा विभाग ने केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने मंगलवार का रातुरोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम पर रखने की योगदान जारखंड जुलाई 2020 को आयोजित किया जाएगा।

शहीद अधिकारी कुमार साहू के नाम पर एक नायकरण की मांग: राज्यीय युवा विभाग ने केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने मंगलवार का रातुरोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम पर रखने की योगदान जारखंड जुलाई 2020 को आयोजित किया जाएगा।

शहीद अधिकारी कुमार साहू के नाम पर एक नायकरण की मांग: राज्यीय युवा विभाग ने केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने मंगलवार का रातुरोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम पर रखने की

ट्रम्प से इतना भय क्यों खा रहे हो, क्या डर है जो छुपा रहे हो!

बादल सरोज

बुहुतई विचित्र समय है। उधर माय डिअर फें ड
ऐसा पिलकर पीछे पड़ा हुआ है कि चुप्प होने का
नाम ही नहीं ले रहा और इधर उनके प्यारे मित्र
मोदी-ऐसी चुप्प साधे हैं कि बोल ही नहीं फूट रहा
न हाँ कहते बन रहा है, न का कहने की हिम्मत
जुटा पा रहे हैं। भारत-पाकिस्तान के बीच हुई
लडाई ज्ञानिसमें अमरीकी गण्डपति को प्रसाणु
युद्ध तक की आशंका दिखाई दे गयी थी ज्ञान में
बीच-बचाव करके, उन्हें डॉट-डपट कर, व्यापार
के लॉलीपॉप दिखाकर, घुड़की देकर युद्धविराम
करवा देने की खुद की उपलब्धि का बखान ट्रॉप्प
बार-बार लगातार कर रहे हैं। इसकी आवृत्ति और
बारम्बारता इतनी है कि अब तो गिनती करना तक
कठिन होता जा रहा है। 10 मई के बाद के 11
दिन में ट्रॉप्प ने 8 बार, हर बार कुछ नया मिर्च-
मसाला जोड़कर युद्धविराम करवाने का दावा
दोहराया। एक देश नहीं, सउदी अरब और कतर
सहित तीन-तीन देशों के सार्वजनिक कार्यक्रमों
में यही बात बोल-बोलकर सार्वजनिक रूप से
भारत को उसकी हैसियत दिखाई है। 23 मई को
न्यूयॉर्क स्थित अमरीका की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से
जुड़े मामलों की संघीय अदालत में तो बाकायदा
शपथपत्र दाखिल करके लिखा-पढ़ी में इसे
उदाहरण के रूप में पेश किया है। टैरिफ बढ़ाने-
घटाने के राष्ट्रपति के निरंकुश अधिकार को
चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में ट्रॉप्प
प्रशासन के प्रतिनिधि ल्यूट्रीनिक ने तीन
न्यायाधीशों की पीठ के सामने शपथ पत्र देकर
टैरिफ नीति की कारगरता बताई। उसने उदाहरण
देते हुए कहा कि "भारत और पाकिस्तान - दो
प्रसाणु शक्ति संपन्न देश जो सिर्फ़ 13 दिन पहले
युद्ध अभियानों में लगे हुए थे - 10 मई, 2025
को एक अनिश्चित युद्ध विराम पर पहुँचे। यह युद्ध
विराम के बल राष्ट्रपति ट्रॉप्प के हस्तक्षेप के बाद ही
हासिल किया गया था और दोनों देशों को पूरी तरह
युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के
साथ व्यापार करने की पेशकश की थी। इस
मामले में राष्ट्रपति की शक्ति को बाधित करने
वाला कोई भी प्रतिकूल निर्णय भारत और
पाकिस्तान को राष्ट्रपति ट्रॉप्प की पेशकश की
वैधता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर सकता
है, जिससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और लाखों लोगों

की जान को खतरा हो सकता है। इस तरह अब भारत को समर्पण करना भी एक नज़र की तरह पेश किये जाने की नौबत आ गयी है। याद रखे कि भारत या पाकिस्तान में से किसी के भी युद्ध विराम का एलान करने के पहले झंसबसे पहले झंजानकारी ट्रम्प ने टिक्टटर एक्स पर दी थी। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक ट्रम्प के मुंह से कोई दर्जन भर बार यह दावा दोहराया जा चुका है - इनमें उपराष्ट्रपति वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा किये गए ऐसे दावों का शुमार नहीं है। इस बीच एक नया ब्यौरा रूस के राष्ट्रपति पुतिन के विशेष सलाहकार यूरी उशाकोव ने जोड़ दिया है, जो ट्रम्प के सीजफायर दावे को प्रामाणिकता देता है। एक इंटरव्यू में उशाकोव ने कहा कि ह्लॉट्रम्प और पुतिन के बीच करीब 75 मिनट की बातचीत हुई, जिसमें परमाणु शक्ति सम्पन्न भारत और पाकिस्तान के बीच जंग एक अहम् मुद्दा थी। इसमें ट्रम्प ने बताया कि किस तरह वह इन दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करवा रहे हैं। भले मोदी, उनके विदेश मंत्री और उनके सरसंघचालक से लेकर शाखा प्रमुख तक इन्हाँने पर भी मुसक्का बांध कर बैठे हों, किन्तु विदेश विभाग के प्रवक्ता रंगीर जायसवाल एक पत्रकार वार्ता में इसे अपरोक्ष रूप से स्वीकार कर चुके हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने माना कि ह्लॉट्रम्प के दैरेन अमरीकी उपराष्ट्रपति वेंस और प्रधानमंत्री मोदी तथा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बातचीत हुई थी, मगर इसमें व्यापार की कोई बात नहीं थी। ह्लॉट्रम्प ने एक प्रश्न के बीच वह स्वीकारेकित छुपी है, जिसका खंडन करने को हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि यह बातचीत मौसम का हाल जानने के लिए नहीं थी - युद्ध रोकने की ही थी! किसी संप्रभु देश, उसमें भी भारत जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाले देश के साथ इस तरह का बर्ताव, तीसरे देशों में जाकर उसका बार-बार दोहराया जाना सिफर कूटीतिक मर्वादाओं का उल्घंघन ही नहीं है, सर्वआम लजित और अपमानित करने वाला भी है। सवाल यह है कि दशकों से आमतौर से आत्मसम्मान की विदेश नीति पर चलने वाले और उसके चलते दुनिया भर में अपनी सम्मानजनक हैसियत बनाने वाले देश के साथ ऐसी नौबत

जुड़ी बताइ गयी हैं। मगर एक तो बात इतनी भर नहीं है और दूसरे ये कि न्यौते को लटकाकर रखने के पीछे सिर्फ कनाडा भर नहीं है ज्ञ अंदरखाने बहुत कुछ हुआ है, डॉल और भी हैं। जी-7 के न्यौते के साथ ही भारत सरकार ने एलान किया है कि वह डालर की जगह किसी स्थानीय करेंसी के उपयोग के ब्रिक्स के प्रस्ताव के साथ नहीं जाएगी। यह मांग असल में अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने मोदी के सामने पत्रकार वार्ता में तब की थी, जब वे उन्हें चुने जाने की बधाई देने गए थे। ट्रम्प ने ब्रिक्स को बंद कर देने तक की हिदायत दी थी और मोदी दन्त-मुख व्यायाम करते रहे थे, जबकि दक्षिण अफ्रीका, यहाँ तक कि यूक्रेन जैसे देश भी ट्रम्प के बड़ोलेपन का जवाब उसके मुंह पर देकर आये थे। ब्रिक्स अमरीकी वर्चस्व वाली एकधृवीयता के मुकाबले के लिए बना संगठन है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। उसके अलावा ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें हैं, कुछ और देश इसमें शामिल हुए हैं और अनेक अन्य देश इसकी सदस्यता की कतार में हैं। ब्रिक्स बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का संगठन है, जिनका दुनिया की जीडीपी में 35% हिस्सा है, जबकि जी-7 का हिस्सा सिर्फ 30% है। ब्रिक्स गठबंधन के देश हर पैमाने से जी-7 देशों की तुलना में मजबूत हैं और लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि इससे उलट जी-7 देशों की अर्थव्यवस्थाएं गिरावट की ओर हैं। वर्ष 2000 में, दुनिया की कुल जीडीपी में जी-7 देशों की हिस्सेदारी 40% से अधिक थी, लेकिन 2024 तक यह 30% से नीचे गिर गई। यह गिरावट मुख्य रूप से चीन, भारत, ब्राजील के आर्थिक विकास के कारण है और मैन्यूफैक्चरिंग से लेकर उपभोग तक चौतरफा है। ब्रिक्स संगठन का एक बड़ा लक्ष्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना है। वैश्विक लेन-देन में डॉलर के प्रभुत्व से इन देशों की असहमति है। डॉलर पर टिकी प्रणाली बाकी देशों को पर्याप्ती प्रतिबंधों के अधीन कर दी रही है। इसलिए ब्रिक्स ने शुरू से ही व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने और गैर-डॉलरीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने का समर्थन किया है। ब्रिक्स देश एक दशक से भी अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की प्रधानता को कम करने की कांशिश कर रहे हैं। बात तो यूरोपियन यूनियन की यूरो जैसी ब्रिक्स की अपनी मुद्रा बनाने तक की हुई है। डॉलर के स्थान पर किसी नई मुद्रा को अपनाने से सबसे अधिक फायदा ब्रिक्स देशों के हो सकता है। हाल के वर्षों में इन देशों ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाने की दिशा में कुछ भले ही सीमित प्रयास किये हैं। खुद भारत अपनी मुद्रा की मांग बढ़ाने के प्रयत्न करता रहा है बड़े तेल उत्पादकों के साथ गैर-डॉलर भुगतान आधारित तेल बित्री पर बातचीत करने का प्रयास किया है। चीन ने सउदी अरब से ऐसे करार किये, भारत ने रुपए में तेल की कीमत तय करने के लिए यूरई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इसी वर्ष ब्रिक्स की बैठक होने वाली है, जिसका जिकरा जी-7 का न्यौता न मिलने पर खुद मोदी प्रचारकों ने बड़े जोर-शोर से किया था; उन्होंने कहा था कि जी-7 में नहीं बुलाया तो क्या, ब्रिक्स में तो जारीबई करेंगे। बात साफ है कि जी-7 से विनियो उजड़ते नवाबों के साथ दस्तरखान पर सिवैयां खाने से पहले ही उसकी कीमत चुकाई जा रही है; हालांकि आशंका बनी हुई है कि जी-7 के पीर मुगा ट्रम्प यहाँ कही इन्हीं के सामने तेरहवीं बार फिर से युद्धविवारण कराने का जिक्र छेड़ दें। अगर कहीं ऐसा हुआ, तो लिखकर रख लीजिये कि मोदी अत्यंत शिष्ट, मुठू और अल्पभाषी व्यक्ति होने का परिचय देंगे और उनके सामने कुछ नहीं बोलेंगे। बैकल मोदी चौथी और यूं पंचवीं अर्थव्यवस्था होने के बावजूद मोदी और उनकी सरकार इतने दबाव में क्यूँ हैं? दक्षिण अफ्रीका में हवाई अड्डे पर रिसीव करने वालों के राष्ट्रपति के न आने, नेपाल के इनके कहने पर चलने से इंकार कर देने, श्रीलंका के अपना रास्ता खुद चुनने जैसी हार बात पर फूफागिरी दिखाने वाले मोदी ट्रम्प और जी-7 के सामने इतने सहमे सहमे से क्यूँ हैं? इसलिए कि उनकी विचारधारा ही समाज्यवाद की मातहती की विचारधारा है। संघ-जनसंघ से भाजपा तक समाज्यवादी अमेरिका इनका आराध्य रहा है। उसके लघेन्दे बनाना इनका सपना रहा है। ट्रम्प युग का अमरीका तो और भी सगा वाला नजर आता है। फिर इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूँजी का अपना ही अल्लोरिथम है। वह सत्ता के साथ अपनी रहीं-सही दिखावी आड़ भी खत्म कर देने की हड़बड़ी में

है। ट्रम्प और मस्क के बीच फूट रही फुलझड़ियाँ इसी की एक झलक हैं। उस पर नकली सोने में फर्जी सुहागा यह है कि इधर वाले के अपने मस्क हैं, जिनका नाम अडानी और अम्बानी है। उन्हें भी अब बड़े अखाड़ों में खेलना है ज्ञ उस एवज में भले ही देश को कितना ही धाया या जोखिम क्यों न उठानी पड़े; उनके राजनीतिक चाकरों को सौ घाज के साथ सौ जूते ही वर्षों न खाने पड़े। अम्बानी और मित्तल को कहार बनाकर स्टारलिंक को अपनी पालकी भारत में पधारने की अनुमति इसी श्रृंखला में देखी जानी चाहिए। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या होगा, लोगों की निजता कितनी बचेगी, इन्स्टरेट की उपलब्धता कितनी महंगी होगी, यह सब चिंताएं देसी और विदेशी कारपोरेट के मुनाफों के बोझ तले दम तोड़ देती हैं। यही है फासीवाद की वह नयी किस्म, जो पूँजी की जनरेशन एक्स के पालने में पलती है। इस सरें डर से ध्यान बंटाना है। जनता का जो हिस्सा और यह बड़ा हिस्सा है ज्ञ इस सबको गलत मानता है, उसे भुलावे में डालना है, तो नरेंद्र सड़कों पर तफरीह करने निकलते हैं। लगभग सारे उद्योग-धंधे, व्यापार-व्यवसाय, बैंक-बीमा विदेशी पूँजी और उसके साथ जुनियर पारंपरी करने वाले देसी धनपिशाचों के हवाले करने के बाद छोटी आँखों वाले गणेश न खरीदने, हर विदेशी माल का बहिकार करने का ऐसा नारा दे रहे हैं, जिसके बारे में उन्हें पता है कि इसे न लागू होना है, न इन्हें करवाना है। इनके मात-पिता संगठन को भी अपने उस स्वदेशी आन्दोलन की सुध आने लगती है, जिसे दशकों पहले स्वयं इन्हीं ने अपने कर कमलों से कब्र में सुलाकर गोभी उगाये थे। यह विचित्र समय है, सचमुच का विचित्र समय !! मगर स्थायी नहीं है। इससे पहले भी ऐसे समय आये हैं, जनता उनसे बाहर निकली है, दुनिया को भी साबुत सलामत बाहर निकाला है। उसके पास कुंजी है ज्ञ एकजुट, जुझारू और कारगर प्रतिरोध की कुंजी। दुनिया भर में इस तरह के उभार सामने आ रहे हैं, खुद अमेरिका भी उबलने के बिंदु तक पहुँच रहा है। भारत के मेहनतकश खास्तौर से पिछली 34 वर्षों के नवउदार युग के संघर्षों की भट्टी से गुरजते हुए सक्षम हो चुके हैं। यही रस्ता है इसी तरह होना चाहिए ऐसा ही होगा।

सपादकाय

लापरवाही की परत दर परत

स्वतंत्रता का पहला शहाद - राना, मा, याद्वा

1858 - वह तारीख

A painting of a woman in traditional Indian attire, wearing a red sari and a yellow headpiece, holding a small object in her hand. The background is a warm-toned landscape.

महिलाओं को युद्धकला में प्रशिक्षित व
एक नया इतिहास रचा। ज़िलकारी बा
सुंदर-मुंदर जैसी वीरांगनाएं उनकी प्रेरणा
रणभूमि में उतरीं और अंग्रेजों के दांत ख
किए। रानी का युद्ध-कौशल और रणनीति
इतनी प्रभावशाली थी कि ब्रिटिश
सेनानायक हूँ रोजे ने स्वयं उनकी प्रशंसा
की। ज़ांसी के किले की रक्षा में रानी ने जिस
अदम्य साहस का परिचय दिया, वह किसी
भी सैन्य इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है।
जब ज़ांसी का किला अंग्रेजों के हाथों
चला गया, तब भी रानी ने हार नहीं मान

सवार होकर वह काल्पी पहुँची। वह तात्या टेपे और अन्य क्रांतिकारियों साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर कब्जा कर लिया। ग्वालियर में रानी केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करती बल्कि अपनी कूटनीतिक सूचिकार्यों को दिखाए दी। किंतु अंग्रेजों को इसी सराय में उन्हें घेर लियाया जून 1858 को, मात्र 29 वर्ष की उम्र में, रानी लक्ष्मी ने अपने अंतिम युद्ध बलिदान दे दिया। कहा जाता है कि विं अंत तक लड़ीं, और अपनी तलवार

'स्टार्टअप्स' के लिए जरूरी है, समझ की तब्दीली

है, लेकिन उसके बाजार में टिकने की सम्भावना नहीं है, ऐसे स्टार्टअप को वित्तीय मदर कौन करेगा? टेक्नालॉजी में अधिकांश नए विचार शोध के क्षेत्र में होते हैं जो विश्वविद्यालयों या विशेष शोध-संस्थानों में किए जाते हैं। इनमें से कई विचारों को बाजार में उतारने में कई बरस या दशक लग जाते हैं तब जाकर स्टार्टअप की कल्पना की जा सकती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विज्ञान एवं टेक्नालॉजी में शोध करने वाले कई असफलताओं से गुजरकर ज्ञान के भंडार को पुख्ता करते हैं। यदि टेक्नालॉजी में शोध की नींव कमज़ोर है तो स्टार्टअप हवा से प्रकट नहीं होंगे। शोध में निवेश करना सरकार का काम है। कई दशकों से चीन इस दिशा में बड़ी मात्रा में निवेश कर रहा है। वर्तमान उदाहरण ही लिं तो इस समय चीन का रिसर्च और डेवलपमेंट का बजट 715 अरब डॉलर है जो भारत से दस गुना अधिक और कई सुनियोजित प्लानिंग के साथ किया गया है। हमारे एक विज्ञान के साथी ने एक घटना सुनाई जो इस बात को दर्शाती है। दो दशक पहले जब वे जर्मनी के एक लैब में अपना पोस्ट-डॉक्टरेट काम कर रहे थे तो उनके जैसे कई स्टूडेंट चीन से थे, पर खास बात यह थी कि चीन के छात्रों के साथ उनकी मदद करने वाले एक सीनियर वैज्ञानिक भी थे जो इस

A hand holding a smartphone displaying a digital wallet interface, overlaid with various financial icons like a bank building, a bar chart, a person icon, a gear, and a gear with a dollar sign.

बात का भी आकलन कर रहे थे कि हम यह लैब चीन में कैसे बना सकते हैं। उन्होंने चीन सरकार को इसकी रिपोर्ट पेश की और एक दशक बाद चीन की यूनिवर्सिटी से उस प्रकार के उच्चतम स्तर के शोधपत्र निकल रहे थे जो इस बात को सिद्ध करता था कि उनके देश में उस प्रकार के लैब बन गए थे। इस एक अन्य उदाहरण से भी समझा जा सकता है। चीन के बाद भारत मोबाइल फोन का सब से बड़ा निर्यातक है, पर दोनों में खास अंतर है। चीन में जब मोबाइल फोन बनता है तो उसका लगभग 90 फीसदी तक नीकी हिस्सा चीन में ही बनाया जाता है। भारत में बनने वाले मोबाइल फोनों के 75 फीसदी तक नीकी पार्ट्स बाहर से आयात किए जाते हैं। इस प्रकार के तकनीकी उद्योग जो मोबाइल फोन के अलग-अलग खास पार्ट्स बना पाएं उनको भारत सरकार एक इको-सिस्टम में नहीं ढाल पाई। तकनीकी उद्योग की नीव में जो शोध होना चाहिए वह भी नहीं बन पाया है। इसका एक कारण है कि हमने इंफास्ट्रक्चर को केवल सड़क, पार्न और बिजली तक सीमित रखा है। ये सब उपलब्ध

ती उद्यमी अपने आप उद्योग का निर्माण न्तु आज के समय के लिए यह समझ इंफास्ट्रक्चर का अहम हिस्सा है तकनीकी और उसमें कृशल मानव संसाधन। यदि उपलब्ध नहीं है तो सरकार का काम है ब्यक्ति करवाए। इसमें सरकार की कई हैं - खुद कारखानों में निवेश करना व गोध के लिए विरोध कदम उठाना और उन नम्ननियों को लाना जिनके पास यह नहीं है। इन कदमों के बिना इस प्रकार के लग सकते। तकनीकी ज्ञान आपको वे कोई नहीं देगा। हम 'मेक इन इंडिया' हते हैं। नारा सही है, पर उसकी कारगर नहीं आती। उद्योग के लिए ज़रूरी है नए लिंगों और एक तरह का जाल या आपसी ने जहाँ एक का सामान दूसरा उपयोग देश के लिए औद्योगीकरण में गहराई है, जब किसी भी सामान को बनाने के पार्ट्स हम देश में बना सकते हैं। यहाँ जना की ज़रूरत है। कुछ क्षेत्रों में सरकार निवेश करना होगा। वर्तमान समय के बताते हैं कि हम कारखानों के लिए ज़रूरी बड़ा हिस्सा आयात कर रहे हैं। चीन पर निर्भर हैं। प्राइवेट सेक्टर को

जब तक सस्ता आयात करने का अवसर रहेगा तब तक वह इस दिशा में निवेश नहीं करेगा। उसकी सोच 'दुकानदारी' की होती है, दूरगमी नहीं। उदाहरण के लिए हम दवा उद्योग के क्षेत्र में अवलम्बन हैं, परन्तु इसका बहुत सारा ज़रूरी सामान चीन से आयात होता है। यदि यही सामान देश में बढ़ाना है तो सरकार को खुद निवेश करना होगा और उसका तकनीकी ज्ञान हासिल करना होगा। हम इस नारे में फंस गए हैं कि सरकार को कारखाने नहीं लगाने चाहिए। नीति जे में ज़रूरी बुनियादी उद्योग की अवधारणा को भूलकर नेहरूवादी आद्योगिकीकरण को नकारा बताने की निर्णयक बहस में मशगूल हो गए हैं। इन सभी कारणों को मिलाकर देखें तो दुकानदारी-नुमा स्टार्टअप का बनना हमारे वातावरण की उपज है। हमने ऐसा माहौल तैयार नहीं किया है जहां सरकार तकनीकी शोध में अधिक निवेश करती हो, जहाँ 'सार्वजनिक क्षेत्र' के उद्योगों द्वारा बुनियादी क्षेत्र में निवेश किया जा रहा हो या फिर विशेष कर्मनियों को टेक्नालॉजी ट्रान्सफर के लिए सरकारी कर्मनी के साथ अनुबंध किया जाए। हमारी नीतियां बाजार व्यवस्था में प्रोत्साहन देने पर टिकी हैं जिससे वातावरण बन जायेगा और निजी क्षेत्र स्वाभाविक रूप से तकनीकी ज्ञान की भरपाई कर लेगा। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है।



जुदा हुए कुशाल टंडन और

शिवांगी जोशी

एक्टर ने दी ब्रेकअप की जानकारी,
बोले- कोई पछतावा नहीं



शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल टीवी के मशहूर एक्टर कुशाल टंडन, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम खूबसूत शिवांगी जोशी कुछ समय से डेट कर रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि दोनों जल्द ही शादी कर सकते हैं, लेकिन अब कुशाल टंडन ने खुद सोशल मीडिया पर शिवांगी के साथ अपने ब्रेकअप की जानकारी दी, हालांकि सोशल मीडिया पर ब्रेकअप की पुष्टि करने के कुछ समय बाद ही कुशाल ने अपनी ये इंस्टाग्राम स्टोरी डिलीट कर दी।

कुशाल टंडन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में साफ-साफ लिखा था, मुझसे प्यार करने वाले मेरे सभी फैंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं और शिवांगी अब एक साथ नहीं हैं। इस बात को अब 5 महीने हो गए हैं। यानी कुशाल ने सीधे तौर पर बता दिया है कि वो और शिवांगी अब अलग हो चुके हैं। इस स्टोरी के तुरंत बाद, उन्होंने अगली स्टोरी में लिखा, मैं सिंगल और खुश हूँ और इस बात का मुझे कोई पछतावा नहीं है। हालांकि, इन दोनों स्टोरीज को कुशाल ने कुछ ही समय बाद हटा दिया, लेकिन ये खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय की आखिरी तस्वीर आई सामने!



बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने 2016 में अपने पति संजय कपूर को तलाक दे दिया था, लेकिन बच्चों के कारण दोनों की मुलाकातें होती रहती थीं, जो करिश्मा के पास रहते हैं। 12 जून की रात जब खबर आई कि करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की डेथ हो गई है तो इस खबर ने हर किसी को हैरानी में डाल दिया। संजय कपूर का निधन पोलो खेलते समय हुआ और पोलो क्लब की तरफ से संजय कपूर की आखिरी तस्वीर एक दिन पहले शेयर की गई है। इस तस्वीर में संजय कपूर हंसते हुए नजर आए।

दिल्ली के रहने वाले बिजनेसमैन संजय कपूर ज्यादातर यूके में ही रहते थे। यहां उन्होंने गार्ड्स पोलो क्लब में Sujan Indian Tigers Polo Team ज्वाइन की हुई थी और पूरी टीम के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। उनके साथ ही संजय अक्सर पोलो खेलने जाते थे। इस क्लब के इंस्टाग्राम पेज पर ही संजय कपूर की आखिरी मुस्कुराती तस्वीर शेयर की गई है और साथ में एक लंबा पोस्ट भी लिखा गया है। इस तस्वीर में सुजान इंडियन टाइगर्स के ऑनर भी नजर आ रहे हैं।

संजय कपूर की आखिरी तस्वीर हुई वायरल

तस्वीर शेयर करने के साथ ही इसके कैशन में लिखा गया, 'आज हम अपने डियर फैंड संजय कपूर की याद में कार्टियर ट्रॉफी का फाइनल खेलेंगे, जिनकी कुछ दिन पहले मैदान पर ट्रैजिकली डेथ हो गई थी। हमारे कैप्टन और संरक्षक, जैसल सिंह अपने पुराने दोस्त संजय कपूर के सम्मान में एक मिनट का मौन रखने के लिए टीम के साथ जाएंगे और फिर सम्मान के प्रतीक के रूप में बाहर बैठेंगे। संजय और जैसल की यह तस्वीर कुछ दिन पहले सेमीफाइनल खेलने के लिए तैयार होने से कुछ समय पहले ही ली गई थी। RIP संजय, आपकी याद आएगी, आपने इस क्लब में जो योगदान दिया वो हमेसा याद रखा जाएगा।'

करिश्मा कपूर और संजय कपूर कब हुए अलग ?

2003 में करिश्मा कपूर ने दिल्ली के रहने वाले बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी। उनके दो बच्चे समायरा और कियान हैं जो पैरेंट्स के तलाक के बाद करिश्मा के पास ही रहते हैं।

संजय कपूर ने तलाक के बाद प्रिया सचदेव से शादी कर ली थी, जिनसे उन्हें एक बेटी भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, करिश्मा कपूर से पहले संजय कपूर ने 1996 में नंदिता महतानी के साथ शादी की थी, जिनसे वो 2000 में अलग हो गए थे।

वर्ष : 13 | अंक : 4 | माह : मई 2025 | मूल्य : 50 रु.

समग्र दृष्टिकोण

(राजनीति एवं युवा उत्कर्ष की मासिक गाथा)

इंसानियत
का
फल



MASALA TEA

Enriched with Real spices



www.sugandhtea.com